रणजीत टाइम्स

इंदौर

बुधवार, 10 जून, 2026

वर्ष 02 | अंक 140 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट पर भारत सक्रिय

पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर से की अहम बातचीत

पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, शांति प्रयासों और भारतीय समुदाय की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच हुई यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में तनाव लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक समुदाय स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है।

क्षेत्रीय हालात पर हुई विस्तृत चर्चा

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के अमीर ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में उभर रही सुरक्षा चुनौतियों और उनके संभावित प्रभावों पर चर्चा की। भारत ने स्पष्ट रूप से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियां क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए चुनौती बन सकती हैं।

भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा

कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ऐसे में बातचीत के दौरान भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के अमीर का धन्यवाद करते हुए कहा कि वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, भलाई और देखभाल के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता और सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया।

कुवैत की संप्रभुता पर हमलों की निंदा

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है और इसका उल्लंघन स्वीकार्य नहीं हो सकता। भारत ने हमेशा सभी देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करने की नीति का समर्थन किया है।

तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि स्थिति को और गंभीर होने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि किसी भी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि तनाव बढ़ने से न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

कूटनीति और संवाद को बताया समाधान

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा कि संघर्ष और सैन्य टकराव की बजाय संवाद का रास्ता अपनाना समय की जरूरत है।

भारत की रणनीतिक चिंता का संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के अमीर के बीच हुई यह बातचीत केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को लेकर भारत की गंभीर चिंता को भी दर्शाती है। भारत के ऊर्जा हित, व्यापारिक संबंध और लाखों भारतीयों की मौजूदगी इस क्षेत्र को नई दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।

शांति और स्थिरता पर भारत का जोर

भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद आधारित समाधान का समर्थक है।

प्रधानमंत्री मोदी की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। भारत का मानना है कि सभी पक्षों को जिम्मेदारी दिखाते हुए बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

CM धामी ने UKSSSC से चयनित 221 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के माध्यम से शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य में बीते साढ़े चार वर्षों में सरकार ने 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम किया है। यह पल युवाओं के वर्षों के परिश्रम और संघर्ष की सफलता का स्वर्णिम क्षण है। उन्होंने कहा कि युवाओं के चेहरों की मुस्कान बताती है कि राज्य सरकार, सही दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य के युवा वर्तमान के साथ भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यरत है। नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नए स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रही है।

अमेरिका में भारतीय पेशेवरों पर मंडराया बड़ा खतरा

नई दिल्ली। अमेरिका में नौकरी कर रहे लाखों भारतीय आईटी पेशेवरों और वहां स्थायी रूप से बसने का सपना देख रहे लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है।

अमेरिकी संसद में एक नया आव्रजन विधेयक पेश किया गया है, जो लागू होने पर H-1B वीजा धारकों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने का रास्ता बेहद मुश्किल बना सकता है। इस प्रस्तावित कानून का सबसे अधिक असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। रिपब्लिकन सांसद Chip Roy ने 'अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट ऑफ 2026' नामक विधेयक पेश किया है।

इस बिल में H-1B वीजा कार्यक्रम को लेकर कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें वीजा की अवधि को छह साल से घटाकर केवल दो साल करना और विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के नियमों को और सख्त बनाना शामिल है।

ग्रीन कार्ड का रास्ता हो सकता है मुश्किल

इस विधेयक का सबसे चर्चित प्रावधान H-1B वीजा के 'डुअल इंटेंट' नियम को समाप्त करना है। वर्तमान व्यवस्था के तहत H-1B वीजा धारक अमेरिका में काम करते हुए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनका स्थायी निवास अमेरिका के बाहर है और वे उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखते। इमिग्रेशन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नियम लागू हो गया तो H-1B से ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया लगभग बंद हो सकती है।

कर्मचारियों और कंपनियों के लिए सख्त शर्तें

प्रस्तावित बिल में कई नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। H-1B कर्मचारियों को 75वें प्रतिशत स्तर के अनुसार अधिक वेतन देना होगा। कंपनियों को यह साबित करना पड़ेगा कि संबंधित पद के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं।

कर्नाटक कांग्रेस में सुलझा विवाद, रामलिंगा रेड्डी ने वापस लिया इस्तीफा

इस्तीफे से जुड़े घटनाक्रम को एक गलतफहमी बताया

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार में मंत्री Ramalinga Reddy ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी Randeep Singh Surjewala ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद मामला सुलझ गया है और रेड्डी मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। सुरजेवाला ने इस्तीफे से जुड़े घटनाक्रम को एक गलतफहमी बताया। उन्होंने कहा कि रेड्डी पार्टी के वफादार नेता हैं और सरकार में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। गौरतलब है कि रेड्डी ने बेंगलुरु विकास मंत्रालय के बजाय सिंचाई विभाग आवंटित किए जाने पर शुक्रवार को इस्तीफे की घोषणा की थी। सुरजेवाला ने बताया कि D. K. Shivakumar, Siddaramaiah और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने रेड्डी से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा द्वारा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।

TMC में संभावित टूट से बदलेगा सियासी गणित?

NDA की ताकत बढ़ने की चर्चा तेज

नई दिल्ली। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली All India Trinamool Congress में असंतोष बढ़ने से कुछ सांसद अलग रुख अपना सकते हैं, जिसका फायदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को मिल सकता है। चर्चाओं के अनुसार, लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसदों में से कुछ सांसद अलग गुट बनाकर NDA का समर्थन कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो लोकसभा में NDA की संख्या और मजबूत हो सकती है। वर्तमान में NDA के पास लगभग 293 सांसदों का समर्थन माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि संभावित समर्थन मिलने पर यह आंकड़ा 300 के पार पहुंच सकता है। इसी बीच परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।

परमाणु रणनीति में बड़ा बदलाव!

भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर हथियार किए तैनात, SIPRI रिपोर्ट से दुनिया में हलचल

नई दिल्ली। वैश्विक सुरक्षा और सामरिक संतुलन के बीच भारत की परमाणु नीति को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दुनिया की प्रतिष्ठित हथियार और सुरक्षा अनुसंधान संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार 12 परमाणु वॉरहेड्स को ऑपरेशनल रूप से तैनात किया है। यह कदम भारत की पारंपरिक परमाणु रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच इसकी व्यापक चर्चा हो रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत की नीति यह रही थी कि परमाणु हथियारों और उन्हें ले जाने वाले डिलीवरी सिस्टम, जैसे मिसाइल या अन्य प्लेटफॉर्म, को अलग-अलग स्थानों पर रखा जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग को केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों तक सीमित रखना और आकस्मिक उपयोग की संभावना को कम करना था। हालांकि SIPRI का कहना है कि अब भारत ने पहली बार कुछ परमाणु हथियारों को ऐसी स्थिति में रखा है जहां उन्हें जरूरत पड़ने पर अपेक्षाकृत कम समय में इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के 12 परमाणु वॉरहेड्स अब "ऑपरेशनली डिप्लॉयड" श्रेणी में माने जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये हथियार केवल भंडारण में नहीं रखे गए हैं, बल्कि उन्हें ऐसी सैन्य व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है जिससे वे तत्काल संचालन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। SIPRI के अनुसार इस बदलाव के पीछे भारत की सामरिक आवश्यकताएं और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां भी एक प्रमुख कारण हो सकती हैं।

दक्षिण एशिया में बदलते सुरक्षा माहौल, पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों और आधुनिक युद्ध तकनीकों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत अपने परमाणु प्रतिरोधक ढांचे को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद अब 'इश्क करो पार्टी' की चर्चा

महुआ मोइत्रा को मिला खास न्योता, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

नई दिल्ली। सोशल मीडिया के दौर में राजनीति और व्यंग्य का मेल लगातार नए रूपों में सामने आ रहा है। हाल के दिनों में चर्चा में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के बाद अब एक और अनोखा नाम सुर्खियां बटोर रहा है—'इश्क करो पार्टी'। इस नए मंच की घोषणा भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश Markandey Katju ने की है।

उन्होंने युवाओं से इस पहल से जुड़ने का आह्वान किया है और इसे "प्यार करो, जंग नहीं" के विचार पर आधारित आंदोलन बताया है। खास बात यह है कि इस नई पहल के साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद Mahua Moitra और वरिष्ठ पत्रकार Mrinal Pande का नाम भी चर्चा में आ गया है, क्योंकि उन्हें इस मंच से जुड़ने का सार्वजनिक निमंत्रण दिया गया है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर राजनीति को लेकर कई तरह के व्यंग्यात्मक अभियान और वैकल्पिक मंच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी क्रम में 'कॉकरोच जनता पार्टी' नामक एक समूह ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों और परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए इस प्रदर्शन के बाद यह नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसी माहौल के बीच अब 'इश्क करो पार्टी' की एंट्री ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जो लोग 'इश्क करो पार्टी' से जुड़ना चाहते हैं, वे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचार और अभियान है, जिसका उद्देश्य समाज में प्रेम, शांति, संवाद और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। उनके अनुसार दुनिया में बढ़ती हिंसा, युद्ध और सामाजिक तनाव के बीच प्रेम और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने की जरूरत है। काटजू ने अपने पोस्ट में इस पहल की रूपरेखा भी साझा की। उन्होंने कहा कि संगठन का मूल संदेश है—"प्यार करो, जंग नहीं।" यह विचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई दशकों से शांति आंदोलनों का हिस्सा रहा है। उनका मानना है कि समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण और कटुता के माहौल में लोगों को जोड़ने के लिए सकारात्मक संदेशों की आवश्यकता है। यही सोच इस मंच के पीछे प्रेरणा का स्रोत बनी है।

इस पहल को लेकर सबसे अधिक चर्चा उस समय शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। इनमें कथित तौर पर मार्कंडेय काटजू तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को संबोधित करते हुए उन्हें 'इश्क करो पार्टी' में शामिल होने का निमंत्रण देते दिखाई दिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि वह अन्य संगठनों और विवादों को भूलकर इस नए मंच से जुड़ जाएं, जिसका एजेंडा प्रेम और शांति को बढ़ावा देना है।

पटना पहुंचते ही गरजे तेजस्वी यादव, सम्राट सरकार पर बोला बड़ा हमला

कानून-व्यवस्था से लेकर राबड़ी आवास तक उठाए सवाल

पटना। बिहार की राजनीति में मंगलवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav अपने पिता Lalu Prasad Yadav और बड़ी बहन Misa Bharti के साथ पटना पहुंचे। राजधानी पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री Samrat Choudhary पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, विकास कार्यों और राबड़ी देवी के सरकारी आवास से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में विकास की रफ्तार पूरी तरह थम चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के पास न कोई स्पष्ट नीति है और न ही भविष्य के लिए कोई ठोस रोडमैप। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें पहले से ही यह भरोसा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी कार्यशैली और सोच में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी "चीफ मिनिस्टर नहीं, बल्कि चीप मिनिस्टर" साबित हो रहे हैं।

राजद नेता ने आरोप लगाया कि बिहार में बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार जनता की मूल समस्याओं को सुलझाने के बजाय दूसरे मुद्दों में लोगों को उलझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार के लिए परेशान हैं और महंगाई ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। इसके बावजूद सरकार के पास इन चुनौतियों से निपटने की कोई प्रभावी योजना दिखाई नहीं देती। तेजस्वी यादव ने शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। उनका आरोप था कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को अवसर देने के बजाय उन्हें निराशा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं से किए गए वादों का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान जो आश्वासन दिए थे, वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के जो दावे किए गए थे, वे केवल घोषणाओं तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई स्थानों पर पेंशन संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं और लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। राबड़ी देवी के सरकारी आवास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर भी तेजस्वी यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि Rabri Devi न केवल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। ऐसे में उन्हें सरकारी आवास और सुरक्षा मिलना पूरी तरह स्वाभाविक है।

20 साल में सड़कों पर बढ़े 32 करोड़ नए वाहन, शहरी परिवहन नीति पर उठे सवाल; विशेषज्ञों ने मांगी नई रणनीति

नई दिल्ली। भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और मोटर वाहनों की रिकॉर्ड वृद्धि ने देश की परिवहन व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। वर्ष 2006 में लागू राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) की समीक्षा के दौरान सामने आए आंकड़ों ने संकेत दिया है कि मौजूदा नीति बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपेक्षित परिणाम देने में सफल नहीं रही। परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि अब देश को नई और व्यापक शहरी परिवहन नीति की जरूरत है, जो आने वाले वर्षों की चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सके। इसी दिशा में Indian School of Public Policy (आईएसपीपी) ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति की समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। संस्था के अनुसार वर्ष 2006 में देश में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 9 करोड़ थी, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 41.3 करोड़ से अधिक हो गई है। इसका अर्थ है कि पिछले दो दशकों में लगभग 32 करोड़ नए वाहन भारतीय सड़कों पर उतरे हैं। वाहनों की यह तेज वृद्धि देश के महानगरों और बड़े शहरों में यातायात दबाव, प्रदूषण और अवसंरचनात्मक चुनौतियों को बढ़ाने वाली प्रमुख वजह बन गई है।

आईएसपीपी के तहत कार्यरत Centre for Urban Transition (आईसीयूटी) द्वारा की जा रही इस समीक्षा में शहरी विकास, परिवहन और सार्वजनिक नीति से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्रारंभिक निष्कर्षों में यह सामने आया कि वर्ष 2006 की नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित साधनों, जैसे साइकिल और पैदल यात्रा, को बढ़ावा देना था। हालांकि, इस दिशा में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो सकी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के अधिकांश शहरों में निजी वाहनों पर निर्भरता लगातार बढ़ी है, जबकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उसी अनुपात में मजबूत नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप सड़कों पर भीड़, यात्रा समय में वृद्धि और ईंधन खपत जैसी समस्याएं गंभीर होती गई हैं। कई शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं का विस्तार तो हुआ, लेकिन उन्हें बस सेवाओं, पैदल मार्गों, साइकिल ट्रैक और भूमि उपयोग योजनाओं के साथ प्रभावी रूप से नहीं जोड़ा गया। इससे परिवहन तंत्र का समग्र विकास नहीं हो पाया।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार के कारण शहरों की परिवहन आवश्यकताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। ऐसे में 20 वर्ष पुरानी नीति वर्तमान चुनौतियों का समाधान देने में पर्याप्त नहीं मानी जा रही।

विशेषज्ञों का मानना

नई नीति में केवल सड़क और मेट्रो परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एकीकृत परिवहन व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है। परिवहन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि वर्ष 2026 में नई राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति लागू की जानी चाहिए। इस नई नीति में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

CM बनते ही बढ़ीं डीके शिवकुमार की मुश्किलें, मंत्रियों की नाराजगी ने खोला कांग्रेस में नए शक्ति संघर्ष का मोर्चा

नई दिल्ली/बेंगलुरु। कर्नाटक की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री D. K. Shivakumar को अपनी ही सरकार के भीतर असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। लंबे राजनीतिक संघर्ष और कांग्रेस नेतृत्व के साथ गहन मंथन के बाद मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे शिवकुमार के सामने अब मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे को लेकर नई चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। सरकार गठन के कुछ ही समय बाद कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है, जिससे कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। सबसे पहले सरकार के वरिष्ठ मंत्री Ramalinga Reddy की नाराजगी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मनाया गया और मामला शांत हो गया, लेकिन अब एक और मंत्री की नाराजगी ने सरकार के भीतर चल रही खींचतान को फिर उजागर कर दिया है।

ताजा मामला मंत्री Krishna Byre Gowda से जुड़ा है। उन्हें बेंगलुरु विकास से संबंधित विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार उनकी नाराजगी विभाग के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को लेकर है।

बताया जा रहा है कि उन्हें ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग तो दिया गया है, लेकिन बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (BMRDA) जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का नियंत्रण मुख्यमंत्री शिवकुमार ने अपने पास रखा है। यही वजह है कि कृष्णा बायरे गौड़ा अपनी शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बेंगलुरु के विकास से जुड़े विभाग राज्य की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनसे जुड़े फैसलों का सीधा असर राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास पर पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि यही विभाग पहले रामलिंगा रेड्डी की नाराजगी का कारण भी बना था। रेड्डी का दावा था कि उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अंतिम समय में यह जिम्मेदारी कृष्णा बायरे गौड़ा को सौंप दी गई और उन्हें सिंचाई विभाग का कार्यभार दे दिया गया। इसी मुद्दे पर उनकी नाराजगी सार्वजनिक रूप से सामने आई थी। इस बीच कांग्रेस के भीतर मंत्री पद की दावेदारी भी तेज हो गई है। अभी भी राज्य मंत्रिमंडल में कई पद खाली हैं और अनेक विधायक मंत्री बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं। इन्हीं संभावनाओं के बीच विधायक Rizwan Arshad भी दिल्ली पहुंचे हैं। रिजवान को डीके शिवकुमार का करीबी समर्थक माना जाता है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वह मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने के लिए पार्टी नेतृत्व से संपर्क साध रहे हैं।

ध्यान ईश्वर की ओर प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा है

वर्तमान समय में ध्यान तथाकथित योग गुरुओं तथा मनोचिकित्सकों द्वारा लोगों को लुभाने का एक उपकरण मात्र बनकर रह गया है। सहजयोग संस्थापिका श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा हमें मार्गदर्शित किया गया है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है बल्कि ध्यान में स्थित होना होता है। ध्यान हमें वैराग्य सिखाता है। अधिकांशतः मनुष्य में चाहना अथवा इच्छाएं ही बलवती होती हैं, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। लौकिक जीवन में कुछ ना कुछ उसे चाहिए ही होता है और जब वह परम शक्तिमान के सामने उपस्थित हो प्रार्थना को तत्पर होता है तो वही सब जो उसके दिमाग में चल रहा है जिसे वह आवश्यक समझता है वही एक के बाद एक उसकी प्रार्थनाओं का हिस्सा होता चला जाता है। जबकि वास्तव में परमात्मा को जानने के बाद, ध्यान में ईश्वर तत्व का एवं अपनी आत्मा में परम तत्व का अनुभव कर लेने के बाद मनुष्य परिपक्व मति हो जाता है। अब वह जान जाता है कि लौकिक जीवन की अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह प्रार्थना का अनमोल समय उसे खोना नहीं है।

वास्तव में परमात्मा से परम मांगना चाहिए अलौकिक मांगना चाहिए, परंतु ध्यान के पूर्व दृष्टि के संकोच के कारण वह बड़ा नहीं सोच पाता। सहजयोग में अत्यंत सरलता से ध्यान के द्वारा आत्मा से साक्षात्कार का अनुभव होता है और हम अपने भीतर गहनता का अनुभव करते हैं यही गहनता हमारी मन बुद्धि को परिपक्व करती है गहरा करती है तब हम प्रार्थना में निर्विचार हो जाते हैं और हमारी ऐसी प्रार्थनाएं फलीभूत भी होती हैं। ध्यान में आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, आप इसमें अकेले हैं यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा है। यह भगवान की ओर एक निजी यात्रा है, आपको अपने भीतर अकेले आगे बढ़ना होता है। लेकिन ध्यान मन में आप अकेले हैं। कोई भी वहां मौजूद नहीं है। एक बार जब आप उस सागर में प्रवेश करते हैं तो आपका परिवार पूरी दुनिया हो जाती है क्योंकि तब हमारा संयोग परम से हो जाता है और तब हमें अहसास होता है कि हम जमीन के किसी एक छोटे से टुकड़े के मालिक नहीं है बल्कि संपूर्ण धरा के स्वामी हैं। इस स्थिति में हमारी प्रार्थनाओं का विस्तार हो जाता है। पर पीड़ा को समझने की गहन शक्ति का विकास हमारे भीतर होने लगता है और तब हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण होने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आइए सहज योग से जुड़ते हैं और सुंदर ध्यान की तकनीक सीख ईश्वर का माध्यम बनते हैं। सहज योग ध्यान केंद्र सदैव सभी नये साधकों का स्वागत करता है। सहज योग के बारे में जानने हेतु हमारा टोल फ्री नंबर है 18002700800 पर कॉल कर सकते हैं सहज योग पूर्णतया निशुल्क है।

जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जीवनदायिनी धारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने लगे तो चिंता स्वाभाविक है

हेमंत भार्गव

शिवपुरी जिले के करैरा नगर में संचालित अनेक आरओ वाटर प्लांटों की कार्यप्रणाली इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। नगरवासियों का आरोप है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के नाम पर कुछ वाटर प्लांट संचालक केवल मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, जबकि पानी की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि नगर में वितरित किए जा रहे आरओ जल की नियमित जांच नहीं हो रही है। पानी में आवश्यक खनिज तत्वों की उपलब्धता, टीडीएस का मानक स्तर, स्वच्छता और शुद्धता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में लोगों के बीच यह आशंका बढ़ रही है कि जिस पानी को वे स्वास्थ्यवर्धक समझकर पी रहे हैं, कहीं वही उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डाल रहा।

नगर के विभिन्न क्षेत्रों में केम्परों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन कई स्थानों पर संचालित आरओ प्लांटों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जल भंडारण टंकियों की सफाई, मशीनों का रखरखाव, गुणवत्ता परीक्षण और लाइसेंस संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कुछ जिम्मेदार प्लांट संचालक गुणवत्ता और शुद्धता को प्राथमिकता देते हुए लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अनेक संचालकों की लापरवाही पूरे क्षेत्र की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि संबंधित विभागों और जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से भी प्रभावी निगरानी दिखाई नहीं दे रही। आमतौर पर किसी बड़ी घटना या जनस्वास्थ्य संकट के बाद ही कार्रवाई की कवायद शुरू होती है, जबकि आवश्यकता समय रहते निरीक्षण और नियंत्रण की है। जनस्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर प्रशासनिक उदासीनता लोगों की चिंता को और बढ़ा रही है। नगरवासियों का कहना है कि आरओ प्लांट संचालकों की प्राथमिकता केवल व्यवसायिक लाभ तक सीमित होती जा रही है। पानी को ठंडा कर बाजार में पहुंचा देना ही मानो उनका उद्देश्य बन गया है, जबकि जनता को मिलने वाले जल की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की कोई गंभीर चिंता दिखाई नहीं देती। जनहित में आवश्यक है कि संबंधित विभाग नगर के सभी आरओ वाटर प्लांटों का नियमित निरीक्षण कराएं, पानी की गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराई जाए तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि शुद्ध पेयजल केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार और स्वस्थ समाज की आधारशिला है। यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में यह लापरवाही जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकती है।

भितरवार में शारदा विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भाजपा के प्रदेश मंत्री आदरणीय भाईसाहब श्री लोकेंद्र पाराशर जी द्वारा प्रतिभाओं का सम्मान किया एवं शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के सम्बन्ध में छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया।

79 साल बाद भी प्यासा पिछोर: आधे नगर तक नहीं पहुंचा नल से जल

महिलाएं और बच्चे ढो रहे पानी

अतुल जैन

25 करोड़ की जलावर्धन योजना पर उठे सवाल, एक दशक बाद भी अधूरी पाइप लाइन; जनता निजी बोर, हैंडपंप और कुओं पर निर्भर

पिछोर। देश की आजादी के 79 वर्ष पूरे होने के बाद भी पिछोर नगर की आधी से अधिक आबादी आज मूलभूत सुविधा पेयजल के लिए संघर्ष कर रही है। एक ओर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पिछोर को जिला बनाने की मांग उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद क्षेत्र के हजारों परिवार आज भी घरों में नल से पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि नगर की महिलाओं और छोटी बच्चियों को सिर पर बर्तन रखकर दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है। नगर परिषद और जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि पिछोर नगर के कई वार्डों में आज तक पेयजल पाइप लाइन नहीं पहुंच सकी है। जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई गई है, वहां भी वर्षों बाद नलों से पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। मजबूरन लोग निजी बोरवेल, हैंडपंप और कुओं पर निर्भर हैं।

(25 करोड़ की योजना बनी सवालों के घेरे में)-पिछोर नगर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग एक दशक पूर्व 25 करोड़ रुपये की लागत से जलावर्धन योजना स्वीकृत की गई थी। योजना के तहत पूरे नगर में पाइप लाइन नेटवर्क बिछाकर प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाना था तथा लोगों को आरओ प्लांट से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी थी। फरवरी 2017 में योजना का कार्य प्रारंभ हुआ था और इसे दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन करीब दस साल बीत जाने के बाद भी योजना अधूरी पड़ी हुई है। कई वार्डों में पाइप लाइन तक नहीं पहुंची, जबकि जहां पाइप लाइन डाली गई है वहां जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।

(वार्डों में बदतर हालात, महिलाओं पर सबसे अधिक बोझ)-नगर के वार्ड क्रमांक 6, 11, 14 और 15 सहित कई क्षेत्रों में आज तक जलापूर्ति की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। वार्ड क्रमांक 11 की आदिवासी बस्ती में रहने वाली महिलाओं को प्रतिदिन लगभग एक किलोमीटर दूर जाकर पानी भरना पड़ता है। सुबह का अधिकांश समय पानी की व्यवस्था करने में निकल जाता है, जिससे मजदूरी और अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल संकट के कारण गर्मी के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है। कई परिवारों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि कुछ लोग निजी साधनों से पानी खरीदने को मजबूर हैं।

(फूटी पाइप लाइन और उखड़ी सड़कें बनी परेशानी)-जिन इलाकों में पाइप लाइन डाली गई है, वहां भी कई स्थानों पर पाइप फूटी हुई पड़ी हैं। परिणामस्वरूप पानी लोगों के घरों तक पहुंचने के बजाय सड़कों पर बह जाता है। इससे एक ओर पानी की बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कीचड़ और गड्ढों की समस्या उत्पन्न हो रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पाइप लाइन बिछाने वाली एजेंसी ने कार्य पूरा होने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं कराई। कई जगह सड़कें खुदी हुई छोड़ दी गईं, जिससे आवागमन में भी परेशानी हो रही है।

(ग्राम पंचायतों से भी बदतर स्थिति)-आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की खबरें सामने आती हैं, लेकिन पिछोर जैसे नगर परिषद मुख्यालय की स्थिति कई ग्राम पंचायतों से भी खराब दिखाई दे रही है। नगर में रहने वाले हजारों नागरिकों को आज भी नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसे प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की विफलता के रूप में देखा जा रहा है।

(जांच और कार्रवाई की मांग तेज)-नगरवासियों ने जलावर्धन योजना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिकों ने मांग की है कि अधूरी पड़ी पाइप लाइन का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए तथा पूरे नगर में नियमित एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

(फैक्ट फाइल)

नगर की कुल जनसंख्या : 22,783
सरकारी हैंडपंप : 175
सरकारी कुएं : 07
जलावर्धन योजना लागत : 25 करोड़ रुपये
योजना प्रारंभ : फरवरी 2017
निर्धारित अवधि : 2 वर्ष
वर्तमान स्थिति : करीब 10 वर्ष बाद भी अधूरी

वाक्स

(कहां पहुंच रहा पानी, कहां नहीं)

(जलापूर्ति वाले वार्ड)

वार्ड 1, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10

(जल संकट वाले वार्ड)

वार्ड 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 एवं 15

(ये बोले जिम्मेदार) -यह बात सही है कि योजना दस साल पहले शुरू हुई थी और आज तक पूरी नहीं हुई है। हम इस संबंध में शासन को 20-25 पत्र लिख चुके हैं। इन पत्रों के माध्यम से समस्या और कमियों की जानकारी लगातार शासन को दी गई है, परंतु शासन स्तर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। खुदी हुई सड़कों के संबंध में एजेंसी को नोटिस जारी किया जा चुका है। हम जल्द ही कार्रवाई भी करेंगे।- आनंद शर्मा शसीएमओ, पिछोर

(ये बोले लोग) -हमारे वार्ड में पानी की पाइप लाइन डले करीब तीन चार साल हो चुके हैं, परंतु आज तक इस पाइप लाइन से पानी नहीं आया है। पीने के लिए काफी दूर से पानी लाना पड़ता है। कई बार शिकायतें कीं, लेकिन आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। - एड. कैलाश नारायण निवासी, वार्ड-13

हमें दो किमी दूर काली माता मंदिर से पीने का पानी लेकर आना पड़ता है। नहाने के लिए हमें मानपुर तालाब पर जाना पड़ता है। हम ग्वालियर तक पानी के लिए शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आज तक हमारे घरों मे पानी नहीं आ पाया है।-(रानी निवासी, वार्ड-11)

एससी-एसटी एक्ट में 6 साल से फरार वारंटी गिरफ्तार, पिछोर पुलिस ने न्यायालय में किया पेश

अतुल जैन

(न्यायालय से जारी था स्थायी वारंट, लोकपाल सिंह तोमर पुत्र रानू राजा दबोचा गया)

पिछोर। पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर फरार वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पिछोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के प्रकरण में पिछले 6 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर सोमवार को माननीय न्यायालय में पेश किया।

(ऐसे पकड़ा गया आरोपी)

एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश, एएसपी संजीव मुले एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नीतू सिंह की टीम लगातार फरार वारंटियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि माननीय न्यायालय श्री अशोक कुमार शर्मा, विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट शिवपुरी द्वारा जारी स्थायी वारंट में फरार आरोपी अपने गांव में है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 09 जून 2026 को आरोपी रानू राजा पुत्र लोकपाल सिंह तोमर उम्र 21 साल निवासी ग्राम नगरेला को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 6 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

(इनकी रही सराहनीय भूमिका)

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नीतू सिंह, सउनि परमाल सिंह, आरक्षक हाकिम वर्मा, आरक्षक प्रदीप नरवरिया, आरक्षक जीतेन्द्र गुर्जर व आरक्षक धर्मेन्द्र लोधी की अहम भूमिका रही। गौरतलब है कि एसपी शिवपुरी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व अधिक से अधिक वारंट तामील कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

CBSE पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'रात-दिन काम करें

शुक्रवार तक निकालें समाधान'

12वीं के छात्रों के भविष्य पर जताई चिंता

नई दिल्ली। 12वीं कक्षा की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के परिणामों में देरी को लेकर Central Board of Secondary Education को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी का सामना करना पड़ा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह प्रभावित छात्रों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए और शुक्रवार तक कोई ठोस समाधान प्रस्तुत करे।

अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जरूरत पड़े तो अधिकारी दिन-रात काम करें, लेकिन छात्रों के भविष्य को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। मामला एक ऐसे छात्र की याचिका से जुड़ा है, जो सऊदी अरब में रहकर सीबीएसई से पढ़ाई कर रहा है। छात्र ने अदालत में गुहार लगाई कि उसकी 12वीं कक्षा की इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम अब तक घोषित नहीं

किया गया है, जिसके कारण उसके विश्वविद्यालय प्रवेश की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। छात्र का कहना है कि उसने विदेश के विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होने से उसका शैक्षणिक भविष्य संकट में पड़ गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस Manmohan और जस्टिस Vijay Bishnoi की पीठ ने सीबीएसई को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि यह केवल एक छात्र का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई छात्र हो सकते हैं जो इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसलिए बोर्ड को व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए समाधान निकालना होगा।

सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया। पीठ ने साफ कहा कि छात्रों के हितों को देखते हुए मामले में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती। अदालत ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार तक ऐसा रोडमैप पेश करे जिससे प्रभावित छात्रों को राहत मिल सके। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राज किशोर चौधरी ने अदालत को बताया कि रिजल्ट घोषित न होने के कारण छात्र की उच्च शिक्षा की योजना प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समय-सीमा तय होती है और यदि परिणाम समय पर उपलब्ध नहीं होता तो छात्र दाखिले का अवसर खो सकता है। इससे उसके पूरे शैक्षणिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू पश्चिम एशियाई देशों में उत्पन्न परिस्थितियों से भी जुड़ा है। क्षेत्र में संघर्ष और अस्थिरता के कारण कई परीक्षाएं प्रभावित हुई थीं। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने पहले एक विशेष मूल्यांकन योजना अधिसूचित की थी। इस योजना के तहत रद्द हुई परीक्षाओं के अंक तिमाही, छमाही और प्री-बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किए जाने थे, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। याचिका में आरोप लगाया गया है कि छात्र के परिणाम की स्थिति बिना किसी स्पष्ट कारण के "RL (Result Later)" दिखाई गई। छात्र ने कई बार बोर्ड से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करने और परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने बार-बार ईमेल और अन्य माध्यमों से संपर्क किया, फिर भी बोर्ड की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

110 रुपये और एक मोबाइल के लिए

बेरहमी की हदें पार: मजदूर का सिर पत्थरों से कुचलकर उतारा मौत के घाट

हैदराबाद। तेलंगाना के सिकंदराबाद से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज 110 रुपये नकद और एक साधारण मोबाइल फोन लूटने के लिए दिहाड़ी मजदूर की निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपितों ने मजदूर के सिर पर बड़े-बड़े पत्थरों से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई दिनों तक चली जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में दो डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर हत्या और लूट की इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 38 वर्षीय जय प्रकाश देशमुख के रूप में हुई है।

जय प्रकाश मूल रूप से दूसरे राज्य के रहने वाले थे और रोजगार की तलाश में हैदराबाद आए थे। वह दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे और अक्सर विभिन्न निर्माण स्थलों पर काम करने के साथ वहीं अस्थायी रूप से ठहरते भी थे। मेहनत-मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले जय प्रकाश को शायद अंदाजा भी नहीं था कि अपने भाई से मिलने की यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी।

जानकारी के अनुसार जय प्रकाश 2 जून को अपने भाई से मिलने के लिए मियापुर पहुंचे थे। दिनभर भाई के साथ समय बिताने के बाद वह सिकंदराबाद क्षेत्र में थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात उन दो युवकों से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें अपना शिकार बना लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते थे और जल्दी पैसे कमाने के लालच में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। 3 जून की तड़के पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे ब्रिज और तुकारामगेट के बीच बाईपास रोड पर एक व्यक्ति खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां का दृश्य बेहद भयावह था। सड़क किनारे जय प्रकाश का शव पड़ा था और उनके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। शव के पास दो बड़े पत्थर भी पड़े मिले, जिन पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। प्रारंभिक जांच में ही स्पष्ट हो गया था कि हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई है। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस धीरे-धीरे आरोपितों तक पहुंचने में सफल रही। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों युवकों ने जय प्रकाश को अकेला देखकर उन्हें निशाना बनाया था। पहले उनसे नकदी और मोबाइल फोन लूटने की कोशिश की गई। जब जय प्रकाश ने विरोध किया तो आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपितों को जय प्रकाश के पास से केवल 110 रुपये नकद और एक सामान्य मोबाइल फोन ही मिला था। लेकिन इतने मामूली सामान के लिए उन्होंने जिस तरह से हत्या की, उसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। लूटपाट के बाद पहचान छिपाने और किसी तरह का प्रतिरोध खत्म करने के लिए आरोपितों ने पत्थरों से सिर कुचलकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपितों की गतिविधियों का विश्लेषण किया और अंततः दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या दोनों पहले भी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं या यह उनकी पहली वारदात थी। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों और मानव जीवन के घटते मूल्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महज 110 रुपये और एक मोबाइल फोन के लिए किसी की जान ले लेना यह दर्शाता है कि लालच और अपराध किस हद तक इंसान को संवेदनहीन बना सकते हैं।

DU प्रोफेसर हत्याकांड में बड़ा खुलासा

फर्जी ID, पुलिस की वर्दी और नकली नोटों का जाल, आरोपी निकला करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड

दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर देबोस्मिता पाल हत्याकांड में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस सनसनीखेज हत्या का मुख्य आरोपित रामप्रसाद दास कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक शातिर ठग है, जिसने वर्षों तक लोगों को अलग-अलग तरीकों से झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया। अब उसके घर से मिले सामान ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। पूर्वी दिल्ली में हुई इस वारदात की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रामप्रसाद दास अपनी पत्नी बनाश्री और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ करीब 1400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से दिल्ली आया था। पुलिस के अनुसार, उसने पूरी योजना बनाकर प्रोफेसर की हत्या को अंजाम दिया। आरोपितों ने घटना से पहले दो बार प्रोफेसर के घर की रेकी की थी और उनकी दिनचर्या पर नजर रखी थी।

जांच के दौरान जब पुलिस ने आरोपित के ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहां से कई चौंकाने वाली चीजें बरामद हुईं। इनमें फर्जी पहचान पत्र, पुलिस की वर्दी, महंगी ब्रांडेड घड़ियां, नकली नोट और अन्य संदिग्ध दस्तावेज शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपित इन सामानों का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने और खुद को प्रभावशाली व्यक्ति साबित करने के लिए करता था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि रामप्रसाद दास करीब दो करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े मामलों में संलिप्त रहा है। इस हत्याकांड की जांच में आधुनिक तकनीक ने भी अहम भूमिका निभाई। आरोपितों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहने थे और हत्या के बाद कपड़े भी बदल लिए थे, ताकि वे सीसीटीवी कैमरों की नजर से बच सकें। हालांकि, इलाके में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से लैस कैमरों ने उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने

जब फुटेज का विश्लेषण किया तो आरोपितों की आवाजाही, हुलिया और गतिविधियों के आधार पर उनकी पहचान सुनिश्चित कर ली गई।

दिलचस्प बात यह रही कि जब पुलिस ने प्रोफेसर के स्वजन को सीसीटीवी फुटेज दिखाई, तो वे आरोपितों को पहचान नहीं सके। इसके बावजूद एआई आधारित विश्लेषण और तकनीकी जांच के जरिए पुलिस आरोपितों तक पहुंचने में सफल रही।

यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपितों ने अपराध को अंजाम देने से पहले पूरी तैयारी की थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए कई स्तर पर सावधानी बरती थी। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को रामप्रसाद दास और उसकी पत्नी बनाश्री को पश्चिम बंगाल के बर्धमान कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया। दोनों आरोपितों को दिल्ली लाकर आगे की पूछताछ की जाएगी। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिनसे न केवल हत्या की पूरी साजिश सामने आएगी, बल्कि ठगी और फर्जीवाड़े के अन्य मामलों की भी परतें खुल सकती हैं। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करें, आधुनिक तकनीक और पुलिस की सतर्क जांच के सामने बच निकलना आसान नहीं है। वहीं, प्रोफेसर देबोस्मिता पाल की हत्या ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

‘18 जून तक इंतजार कीजिए...’ राज्यसभा चुनाव पर BAP विधायक

कमलेश्वर डोडियार का बड़ा बयान, लापता होने की चर्चाओं पर तोड़ी चुप्पी

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। तीसरी सीट के लिए होने वाले मुकाबले ने प्रदेश की राजनीति में नया उत्साह और हलचल पैदा कर दी है।

इसी बीच भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के एकमात्र विधायक कमलेश्वर डोडियार को लेकर चल रही अटकलों और उनके कथित रूप से ‘लापता’ होने की खबरों के बीच उन्होंने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर साझा की गई उनकी एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा जोरों पर थी कि राज्यसभा चुनाव की रणनीतिक गतिविधियों के बीच कमलेश्वर डोडियार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे थे और उनके ठिकाने को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही थीं। इन तमाम अटकलों के बीच डोडियार ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चुप्पी तोड़ी और स्पष्ट संकेत दिया कि फिलहाल वे अपने राजनीतिक पत्ते खोलने के मूड में नहीं हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में डोडियार ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने किसे वोट दिया है, इसकी जानकारी वे 18 जून को ही देंगे। उन्होंने मुख्यधारा के मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से जुड़े उनके फैसले का खुलासा निर्धारित समय पर किया जाएगा। इस बयान के साथ ही उन्होंने उन लोगों पर भी तीखा हमला बोला जो लगातार उन्हें सलाह देने या उनके राजनीतिक फैसलों पर टिप्पणी करने में लगे हुए हैं।

ऐसे में यह सवाल उठने लगे थे कि आखिर राज्यसभा चुनाव में उनका रुख क्या होगा और वे किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे।

डोडियार की पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने अपने आलोचकों और सलाह देने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग उन्हें राजनीतिक सुझाव दे रहे हैं, उन्हें पहले जमीनी राजनीति में अपनी क्षमता साबित करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को पहले पंच या पार्षद का चुनाव जीतकर दिखाना चाहिए, उसके बाद ही वे किसी विधायक को सलाह देने की स्थिति में होंगे। दरअसल, राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने अपने विधायकों को एक साथ रखने के उद्देश्य से उन्हें चार्टर्ड विमान के जरिए बेंगलुरु भेजने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर, विपक्षी दल भी अपने-अपने स्तर पर संख्या बल और समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में कमलेश्वर डोडियार जैसे एकमात्र विधायक का वोट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा की तीसरी सीट के चुनाव में हर वोट की अहम भूमिका हो सकती है। डोडियार के संपर्क में न होने और उनके मोबाइल फोन बंद आने की खबरों ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी थी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वे किस राजनीतिक खेमे की ओर झुकाव रख सकते हैं। हालांकि अब उनके सार्वजनिक बयान के बाद यह साफ हो गया है कि वे फिलहाल किसी भी तरह का खुलासा करने के पक्ष में नहीं हैं और उन्होंने पूरे मामले को 18 जून तक रहस्य बनाए रखने का फैसला किया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डोडियार का यह बयान राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्सुकता और बढ़ाने वाला है। उनकी ओर से वोटिंग संबंधी निर्णय का खुलासा टालने से राजनीतिक दलों और पर्यवेक्षकों की नजरें अब 18 जून पर टिक गई हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट और उसमें इस्तेमाल किए गए तीखे शब्दों को लेकर भी बहस जारी है। फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव के इस सियासी मुकाबले में कमलेश्वर डोडियार की भूमिका चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। आने वाले दिनों में उनका अंतिम रुख क्या होगा और उनके वोट का राजनीतिक समीकरणों पर कितना असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर BJP की आपत्ति

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजधानी भोपाल से एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज करा दी है। इस आपत्ति के बाद विधानसभा परिसर में दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भारी हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली।

विधानसभा पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने की खबर मिली, कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ तुरंत विधानसभा परिसर पहुंचा। निर्वाचन कक्ष में डटे बीजेपी नेताः बताया जा रहा है कि विधानसभा के निर्वाचन कक्ष के भीतर पहले से ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जो आपत्ति की प्रक्रिया को लेकर चर्चा कर रहे थे। जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और पदाधिकारी निर्वाचन कक्ष के भीतर जाने लगे, तो उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई।

निर्वाचन कक्ष के बाहर जबरदस्त हंगामा

कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने से रोके जाने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। विधानसभा परिसर देखते ही देखते राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। अंदर जाने से रोके जाने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा निर्वाचन कक्ष के ठीक बाहर मोर्चा खोल दिया और बीजेपी व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख वहां तैनात पुलिस बल ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई।

नामांकन पर सस्पेंस बरकरार

बीजेपी द्वारा मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर किस तकनीकी या कानूनी आधार पर आपत्ति उठाई गई है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

भोजशाला पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा: बोले- यहां का खंभा-खंभा चीखकर कह रहा है कि मैं मंदिर हूं, मुस्लिमों से की सच स्वीकारने की अपील

धार। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से विधायक और प्रखर हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा आज धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर में दर्शन-पूजन किया और आरती में शामिल हुए। इस दौरान भोजशाला परिसर में तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भोजशाला का खंभा-खंभा चीख-चीखकर गवाही दे रहा है कि यह एक हिंदू मंदिर है।

‘खिलजी से लेकर अब तक मंदिर खंडित करने के षड्यंत्र हुए’

विधायक रामेश्वर शर्मा ने धार के हिंदू समाज की सराहना करते हुए कहा- भोजशाला की यह भव्य और दिव्य इमारत मां सरस्वती का पावन मंदिर है। इस पवित्र मंदिर को खंडित करने का षड्यंत्र अलाउद्दीन खिलजी के समय से लेकर अभी तक कई लोगों द्वारा लगातार किया जाता रहा। मैं धार के हिंदुओं को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस संघर्ष को 700 साल तक जिंदा रखा। उन्होंने सड़कों पर लड़ाई भी लड़ी और न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाया। ऐतिहासिक तथ्यों और सत्य को स्वीकार करते हुए हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया है।

मुस्लिम समाज सच स्वीकारे

रामेश्वर शर्मा ने मुस्लिम समुदाय से अपील की। मैं मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि वे थोड़ा समझें, इतिहास के तथ्यों और सत्य को स्वीकार करें। यह राजा भोज द्वारा बनाया गया मां सरस्वती का भव्य और दिव्य मंदिर है। वे इस भोजशाला को हिंदुओं को सौंप दें और आपस में

गले मिलें। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी जोड़ा कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो धार के हिंदुओं से देश का हर हिंदू प्रेरणा लेगा। पूर्वजों द्वारा इतिहास में की गई गड़बड़ियों का परिणाम उन सभी स्थानों पर दिखाई देगा।

धार में बनेगा ‘सरस्वती लोक’

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा धार में ‘सरस्वती लोक’ बनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार इस पावन धरा के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजा भोज की इस ऐतिहासिक राजधानी और कर्मस्थली में संस्कृति व सभ्यता को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे।

इंग्लैंड से वापस लाएंगे प्रतिमा

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मां वाग्देवी की जो मूल प्रतिमा वर्तमान में इंग्लैंड (ब्रिटिश म्यूजियम) की धरती पर है, उसे आज नहीं तो कल भारत की भूमि पर वापस लाया जाएगा।

इंदौर बना वैश्विक कृषि संवाद का केंद्र

इंदौर बना वैश्विक कृषि संवाद का केंद्र, BRICS कृषि महाकुंभ में 58 करोड़ किसानों के भविष्य पर होगा मंथन

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मंगलवार से शुरू हुए BRICS कृषि सम्मेलन ने शहर को वैश्विक कृषि संवाद के केंद्र में ला खड़ा किया है। पांच दिनों तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में ब्रिक्स और सहयोगी देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और नीति निर्धारक खेती-किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

इंदौर। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी सहयोग, टिकाऊ खेती और छोटे किसानों की चुनौतियों पर साझा रणनीति तैयार करना है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के माध्यम से दुनिया के लगभग 58 करोड़ किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े नीति निर्माताओं तक हरित विकास, टिकाऊ कृषि और तकनीकी नवाचार का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान तैयार होने वाली सिफारिशें और संयुक्त घोषणा भविष्य में कृषि सहयोग की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देश आज विश्व के विकासशील देशों की एक प्रभावशाली आवाज बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की लगभग 42 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है और वैश्विक कृषि उत्पादन में भी इनकी हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से अधिक है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर इन देशों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि विश्व के लगभग 58 करोड़ किसानों में से करीब 70 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान ब्रिक्स देशों में रहते हैं। ऐसे में इन किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साझा प्रयासों की आवश्यकता है।

सम्मेलन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम के तहत 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की अधिकारी स्तर की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जबकि 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक होगी। इस दौरान कृषि अनुसंधान, जैविक खेती, कृषि तकनीक, जल संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि व्यापार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के समापन पर एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, जिसमें सदस्य देशों के बीच भविष्य के सहयोग और साझा रणनीति का खाका प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील, इथियोपिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे हैं। सोमवार रात विदेशी मेहमानों का स्वागत मालवा की प्रसिद्ध छप्पन दुकान पर पारंपरिक अंदाज में किया गया। मेहमानों ने मालवी व्यंजनों का स्वाद लिया और इंदौर की सांस्कृतिक विरासत से परिचित हुए। उन्हें शिकंजी, दही बड़ा, शाही पोहा, कचौरी, पेटिस और साबूदाना खिचड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन परोसे गए।

लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तैयार, 12 जून से नए भवन से शुरू हो सकता है ट्रेनों का संचालन

इंदौर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से विकसित किए जा रहे लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। लंबे समय से चल रहे पुनर्विकास कार्य के बाद रेलवे प्रशासन 11 जून को यार्ड रीमॉडलिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्टिंग का महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है। यदि यह प्रक्रिया तय समय के अनुसार पूरी हो जाती है, तो 12 जून से ट्रेनों का संचालन नए स्टेशन भवन से शुरू किया जा सकता है। इससे यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और आधुनिक रेलवे स्टेशन का लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन के पुनर्विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण ऑपरेटिंग, सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम को पुराने भवन से नए भवन में स्थानांतरित करना है। इसी उद्देश्य से 11 जून को विशेष ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान रेलवे के तकनीकी और संचालन से जुड़े कई कार्य एक साथ किए जाएंगे, ताकि भविष्य में ट्रेनों का संचालन सुचारु और सुरक्षित तरीके से किया जा सके।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि लक्ष्मीबाई नगर यार्ड के फेज-2 रीमॉडलिंग कार्य के तहत यह ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कारण 11 जून को कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। कुछ पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त किया गया है, जबकि कई डेमू ट्रेनों को सीमित दूरी तक ही चलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित करने की योजना बनाई गई है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। रेलवे सूत्रों के अनुसार, नई स्टेशन बिल्डिंग का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भवन को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया गया है, जिसमें यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का

विशेष ध्यान रखा गया है। स्टेशन परिसर में बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक टिकटिंग व्यवस्था, उन्नत प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता सुविधाएं और यात्रियों के लिए आसान आवागमन की व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी कड़ी में लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को भी आधुनिक स्वरूप दिया गया है। रेलवे का उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना भी है। नए स्टेशन के शुरू होने से इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। 11 जून को होने वाले तकनीकी कार्य के दौरान रेलवे की विभिन्न टीमें यार्ड, सिग्नलिंग सिस्टम, कंट्रोल नेटवर्क और ऑपरेटिंग सुविधाओं को नई बिल्डिंग से जोड़ने का काम करेंगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह सफल रहने पर अगले ही दिन से स्टेशन का संचालन नए परिसर से शुरू किया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप इंदौर के रेलवे बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा।

सराफा चौपाटी में हाथ धोने को लेकर शुरू हुआ विवाद बना बवाल

युवकों ने एक-दूसरे पर बरसाईं कुर्सियां; 6 आरोपी हिरासत में

इंदौर। देशभर में अपनी रात्रिकालीन फूड स्ट्रीट के लिए प्रसिद्ध इंदौर की सराफा चौपाटी में देर रात एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। हाथ धोने के दौरान पानी के छींटे पड़ने की बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों के युवकों के बीच इतना तनाव बढ़ गया कि उन्होंने एक-दूसरे पर कुर्सियों से हमला करना शुरू कर दिया। घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सराफा चौपाटी पर देर रात बड़ी संख्या में लोग खाने-पीने और घूमने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान दो युवकों के बीच हाथ धोने के समय पानी के छींटे पड़ने को लेकर बहस शुरू हुई। शुरुआत में मामला केवल कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के अन्य साथी भी विवाद में शामिल हो गए। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

विवाद बढ़ने के साथ ही युवकों ने आसपास रखी कुर्सियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं और कई युवकों ने कुर्सियों से हमला भी किया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से चौपाटी पर मौजूद लोग घबरा गए। कई परिवार और पर्यटक अपनी सुरक्षा के लिए वहां से दूर हट गए। कुछ समय के लिए पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के युवक एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद शहर में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई। सूचना मिलते ही सराफा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल युवकों की पहचान शुरू की।

जांच के बाद दोनों पक्षों के कुल छह युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मारपीट, शांति भंग करने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद किसी बड़ी रंजिश का परिणाम नहीं था, बल्कि एक मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था। हालांकि दोनों पक्षों ने संयम खो दिया, जिसके कारण मामला हिंसक हो गया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर भी घटना की विस्तृत जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मारपीट में और कौन-कौन लोग शामिल थे। सराफा चौपाटी इंदौर की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है, जहां रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं।